इंटरनेशनल प्राइस में तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ाने में जुटीं शुगर मिलें

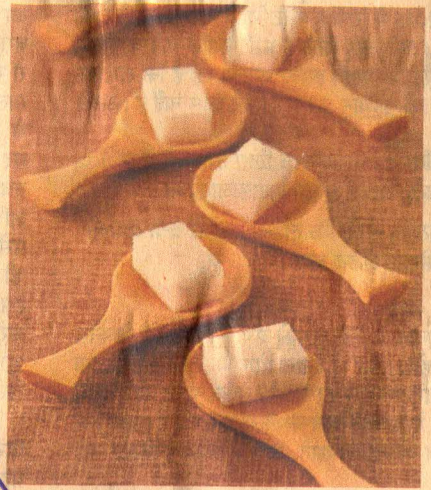

[जयश्री भोसले | पुणे]

इंटरनेशनल प्राइसेज में सुधार आने के बाद चीनी मिलों ने पिछले 10 दिनों में लगभग एक लाख क्विंटल चीनी के एक्सपोर्ट के लिए डील साइन की हैं। ब्राजील में पेराई शुरू होने और उससे इंटरनेशनल प्राइसेज पर असर पड़ने से पहले चीनी मिलें इस मौके का अधिकतम फायदा उठना चाहती हैं।

महाराष्ट्र कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बाबर ने बताया, 'एक्सपोर्टर्स चीनी के लिए 26.50 रुपये तक के रेट की पेशकश कर रहे हैं और इस वजह से मिलें अब एक्सपोर्ट करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। मिलों ने लगभग एक लाख क्विंटल चीनी के एक्सपोर्ट के लिए डील साइन की हैं और जल्द ही कुछ और डील्स भी होंगी।' केंद्र सरकार की ओर से गन्ने के भुगतान पर

एक्सपोर्टर्स चीनी के लिए 26.50 रुपये तक के रेट की पेशकश कर रहे हैं और इस वजह से मिलें अब एक्सपोर्ट करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं

संजीव बाबर
MD, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज फेडरेशन

45 रुपये प्रति टन सब्सिडी के रूप में मिलेंगे और ऐसे में मिलों को प्रति क्विंटल लगभग 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

डोमेस्टिक मार्केट में चीनी के दाम 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर हैं और ऐसे में एक्सपोर्ट से मिलने वाला रिटर्न डोमेस्टिक मार्केट के बराबर है। अहमदनगर जिले की वृद्धेश्वर एसएसके के मैनेजिंग डायरेक्टर जे आर पवार ने बताया, 'हमने तीन मार्च को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर 26,000 क्विंटल के लिए एक्सपोर्ट डील साइन की है।'

हालांकि, एक्सपोर्टर्स का मानना है कि उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में ब्राजील की चीनी आने से पहले तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। ईडी एंड एफ मैन (इंडिया) के मैनेजिंग डायरेक्टर राहिल शेख ने कहा, 'भारतीय मिलों को अभी जितना अधिक संभव हो व्हाइट शुगर का एक्सपोर्ट करना होगा। ब्राजील की चीनी के इंटरनेशनल मार्केट में आने के बाद हमारे लिए लो क्वॉलिटी व्हाइट शुगर को बेचना मुश्किल होगा।'

देश से चीनी के एक्सपोर्ट के लिए माहौल बेहतर होने की वजह से इंडस्ट्री को अब अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट करने की उम्मीद है। एमएनसी एक्सपोर्ट हाउस सकडेन के मैनेजिंग डायरेक्टर यतिन वधवाना को उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार के चीनी मिलों का एक्सपोर्ट कोटा कम करने के फैसले के बाद देश से चीनी का कुल एक्सपोर्ट बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का दबाव कम होने से अब 15-20 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट हो सकता है। पहले केवल 15 लाख टन के एक्सपोर्ट का अनुमान था।उन्होंने कहा कि मॉनसून के आने से पहले अधिक एक्सपोर्ट होगा क्योंकि मॉनसून के दौरान चीनी बाहर भेजना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र की चीनी मिलों ने एक्सपोर्ट के अपने अनिवार्य कोटा को कम करने की मांग की थी, जिसे राज्य सरकार ने मान लिया। इससे महाराष्ट्र की मिलों के एक्सपोर्ट टारगेट में कमी आएगी क्योंकि इस वर्ष सूखे की वजह से उनका प्रॉडक्शन घटा है।